

पहले मुख्य समाचार।

- केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने सीएसआईआर के स्टार्ट अप कॉन्क्लेव में की प्रदेश में बायो टेक्नोलॉजी पार्क और साइंस म्यूजियम खोले जाने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा-समाज को नई दिशा दिखा रहे हैं सीएसआईआर के चारों संस्थान।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। वक्फ संशोधन अधिनियम दो हजार पचीस के कुछ प्रावधानों को भी स्थगित किया।
- एक अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले पंद्रह मिनट के दौरान केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से कर सकेंगे टिकट बुकिंग।
- स्वच्छता के मानचित्र पर बदल रही है देश की तस्वीर। खुले में शौच की कुरीति के खात्मे से प्रतिवर्ष सत्तर हजार शिशुओं की मृत्यु रोकने में मिली सफलता।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-सीएसआईआर के स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवसाय के लिए सुरक्षा, सुगमता और मजबूत ईको सिस्टम जरूरी है और यह तीनों उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में स्थित सीएसआईआर के चारों संस्थान अपने अनुसंधान से देश और प्रदेश के किसानों तथा समाज को नई दिशा दिखा रहे हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमें जितना अधिक इन्वेंशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, दुनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा। और ये हमारा सौभाग्य है। सीएसआईआर की चार महत्वपूर्ण लैब्स एनबीआरआई, सीडीआरआई, आईटीआर और सी मैप ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बायो टेक्नोलॉजी पार्क और साइंस म्यूजियम खोले जाने की भी घोषणा की।

भारत वर्ष में जो बी टाउन है, जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर आकांक्षा का स्तर बहुत ऊँचा है, एस्पिरेशनल लेवल बहुत ऊँचा है। लगभग पचास प्रतिशत हमारे स्टार्टअप टायर टू और टायर थ्री सिटी से आ रहे हैं। जिस तरह से आपने स्टॉल्स देखे होंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका काफी अधिक पोर्टेबिलिटी है। मेरी कल्पना है कि जिस तरह से हैदराबाद विकसित हुआ है दक्षिण भारत में उसी तरह का पोर्टेबिलिटी और क्षमता लखनऊ में है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कल वक्फ कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम दो हजार पचीस के कुछ प्रावधानों को स्थगित भी कर दिया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बनाने से पहले पांच साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता वाले खंड पर रोक लगा दी गई। न्यायालय ने आदेश दिया कि यह खंड तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस शर्त के निर्धारण के संबंध में कोई समुचित नियम नहीं बना लेती हैं। एक रिपोर्ट-

सरकार ने नामित अधिकारी को यह निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई है, कि क्या कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करती है। वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों के नामांकन को अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई। न्यायालय ने कहा कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का पदेन सदस्य मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणियाँ केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।

इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इसी महीने की तीन तारीख को उनका यह सपना तब साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दीं। प्रस्तुत है ऐसी वस्तुओं पर आधारित विशेष रिपोर्ट, जिन पर जीएसटी बारह प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।

नई जीएसटी सुधारों के तहत दस्ताने खेल कीट जैसे सामान्य शारीरिक व्यायाम जैसे उपकरण तथा मछली पकड़ने के समान पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने कृषि आधारित लकड़ी उत्पाद जैसे बांस के फर्श, बैरल तथा लकड़ी के टब आदि पर भी कर की दर को पांच प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 12 प्रतिशत हुआ करती थी।

आने वाले मुख्य त्योहारों से पहले जीएसटी में किए गए इन सुधारों से आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा और देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा मोहन के साथ दिलनशी आरजू आकाशवाणी समाचार दिल्ली।

रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि पहली अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले पंद्रह मिनट के दौरान, केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट और उसके ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। एक रिपोर्ट—

वर्तमान में, यह पाबंदी केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि टिकट आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुँच सकें और इसका दुरुपयोग न हो। हालाँकि, मंत्रालय ने यह भी कहा कि वर्तमान में भारतीय रेलवे के कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर्स के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। सामान्य आरक्षण खुलने के दस मिनट के दौरान रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले की तरह आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।

जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सेवा पर्व में, हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव लाया है।

स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए ग्यारह साल बीत चुके हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लालकिले की प्राचीर से शौचालय क्रांति की बात होगी, लेकिन पंद्रह अगस्त 2014 के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसा कर दिखाया।

स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी दो अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और चार साल के भीतर-भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक काम को तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूँ और वो है हिन्दुस्तान के सभी स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियाँ स्कूल छोड़कर भगेंगी नहीं।

प्रसिद्ध नेचर पत्रिका में हाल ही एक शोध निबंध प्रकाशित हुआ है। इस शोध को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भारत में खुले में शौच के खत्म होने के बाद आ रहे बदलावों पर अध्ययन किया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि शौचालय क्रांति से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। शोध पत्र में कहा गया है कि खुले में शौच की कुरीति के खत्म होने से सालाना करीब 70 हजार शिशुओं की मृत्यु रोकने में सफलता मिली है।

स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बारह करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। इसके साथ ही देश खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त हो गया है। हर घर नल जल योजना के तहत देश के करीब 78 प्रतिशत घरों तक पाइप के जरिए साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के शहरों को 2026 तक कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तो स्वच्छता का अभियान के तहत वार्षिक स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहे हैं। इसका असर है स्वच्छता के मानचित्र पर भारत की तसवीर अब पहले से बहुत बदल चुकी है।

प्रदेश के कई जिलों में कल से रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में कहीं कहीं रुक रुक कर आज भी वर्षा का क्रम जारी है। लखनऊ सहित कुछ अन्य जिलों में कल सुबह से शुरू हुई रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस बीच, बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियाँ उफान पर हैं। इसकी वजह से इस समय बलिया, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी समेत प्रदेश के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
